नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02
अंक : 008
दि. 08.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पटना में हुआ पीएम मोदी का भव्य रोड शो, भारी संख्या में मौजूद लोगों ने फूल बरसा कर किया स्वागत

(जीएनएस)।

पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में सम्राट सरकार का विस्तार हुआ। उससे पहले पीएम मोदी पटना पहुंचे और रोड शो किया। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूल बरसा कर पीएम मोदी का स्वागत किया। पटना के गांधी मैदान में शपथग्रहण हुआ, लिहाजा सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक कदम-कदम पर जश्न और जोश की तस्वीरें नजर आईं।

पीएम मोदी ने पटना की सड़कों पर जब यह रोड शो किया, तब पार्टी की खुशी दोगुनी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो इधर बिहार में पहली बीजेपी सरकार का विस्तार हुआ। ऐसे में पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल दिखा। यहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आई। यहां कुल 32 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं।

पटना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और इखढ अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से इस कार्यक्रम का सियासी महत्व और बढ़ गया।

जान लें कि पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक ढट मोदी के रोड शो का रूट था। उनका रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ और इसके बाद, यह हार्डिंग रोड, वीरचंद्र पटेल पथ और आयकर चौराहे से होते हुए पटना के मशहूर गांधी मैदान तक पहुंचा। इस पूरे रास्ते पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ढट मोदी के रोड शो के दौरान, बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने जुटे।

गौरतलब है कि ढट मोदी करीब 6 महीने के बाद पटना आए। इससे पहले वे 20 नवंबर को पटना आए थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह कार्यक्रम भी पटना के गांधी मैदान में हुआ था।

पटना में मोदी-नीतीश की केमिस्ट्री! पीएम के इशारे पर सम्राट ने नीतीश को बुलाया, फिर मंच पर दिखा याराना

पटना में अद्भुत राजनीतिक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मंच के केंद्र में बुलवाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कंधे पकड़कर और मुस्कुराते हुए जिस गर्मजोशी से मुलाकात की। पटनाः बिहार की राजनीति में आज का दिन न केवल नई कैबिनेट के गठन के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के मजबूत संबंधों के लिए भी याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के आज एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों के साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प को सलाम किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता, तत्परता और समन्वित शक्ति को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इससे बलों की एकजुटता प्रदर्शित हुई है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती का भी पता चलता है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया कि भारत आतंकवाद को हराने और उसे

पनपने में मदद करने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर हम पहले की तरह ही अडिग हैं।"

श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और भारत की जनता पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को सशस्त्र बलों पर गर्व है।

सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सफलता को दशार्ते हुए, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को उनके द्वारा साझा की गई तस्वीर से बदल दें।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कियाः 'एक साल पहले, #ऑपरेशनसिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है।

ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इसने हमारे सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता, तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। साथ ही, इसने हमारे बलों के बीच बढ़ते समन्वय को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया।

आज, एक साल बाद भी, आतंकवाद को हराने और उसे पनपने में मदद करने वाले पूरे तंत्र को समूल नष्ट करने के अपने संकल्प पर हम पहले की तरह ही अडिग हैं।"

'एक साल पहले, #ऑपरेशनसिंदूर के दौरान, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और हमारे लोगों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया। हर भारतीय को हमारी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है।

प.बंगाल में विधानसभा भंग, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो गया. कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, जिसके साथ ही ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद भी समाप्त हो गया. इस्तीफे को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच यह फैसला सीधे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ, जिससे बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया है और यह फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में न कैबिनेट बची है और न ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर हैं. इस्तीफे को लेकर चल रही खींचतान के बीच यह बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ.

गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया है. इस नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं. विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में बीते 15 साल से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन अब खत्म हो गया है.

अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ये अनुच्छेद 174(2)(b) क्या है, जिसके दम पर राज्यपाल ने इतना बड़ा फैसला लिया? दरअसल, भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने की सबसे बड़ी ताकत देता है. इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में विधानसभा को समय से पहले भंग कर नए चुनाव या नई सरकार का रास्ता साफ कर सकते हैं. इसमें राज्यपाल को सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने की भी शक्ति मिलती है. हालांकि, राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप न हो. सीधा मतलब यह है कि जब सदन में कोई पार्टी बहुमत साबित न कर पाए या जनादेश बदल जाए, तब राज्यपाल इसी अनुच्छेद का 'हंटर' चलाकर पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हैं, जैसा आज बंगाल में देखने को मिला.

कुर्सी पर जिद के बीच राज्यपाल का आदेश

राज्यपाल का यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली करारी हार को मानने को तैयार नहीं थीं और इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे. लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के आगे यह स्थिति ज्यादा देर नहीं टिक सकी. विधानसभा भंग होते ही उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप खत्म हो गया. अब जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा.

पूर्व केंद्रीय सचिव जवाहर सरकार के मुताबिक, यह कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है, बल्कि एक बीच की व्यवस्था यानी 'इंटरिम अरेंजमेंट' है. जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्यपाल ही शासन की कमान कामकाज सीधे राजभवन की देखरेख में होगा.

बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रात 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे. उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि वह नई सरकार के गठन और 9 मई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

ममता का इस्तीफे से इनकार

इससे पहले ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते सियासी खींचतान जारी थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए कैबिनेट और विधानसभा को भंग कर दिया।

तीन बार सीएम रह चुकीं ममता

ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता में थीं और तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका कार्यकाल विवादों, हिंसा और विकास योजनाओं के मिश्रण के लिए जाना जाता है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत

ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद सीएम योगी का अपने पैतृक गांव पंचूर जाने का कार्यक्रम है। पंचूर में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम शुक्रवार को है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को वापस लौटेंगे।

'2027 में पंडित जी सपा सरकार बनवाएंगे', अखिलेश यादव ने बता दिया अपने मिशन यूपी का फॉर्मूला

(जीएनएस)।

लखनऊः देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आ गए हैं। 5 राज्यों में 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं जीता है। तमिलनाडु से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। वहीं, विपक्ष के लिए पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा झटका रहा है। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री थीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने हरा दिया है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए अखिलेश यादव अलर्ट मोड पर आ गए हैं।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2012 में कैसे सपा सरकार बनी थी, वही फामूर्ला 2027 के यूपी चुनाव में लागू करने की बात कही। इसी मंत्र से अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश

यादव ने कहा कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अकपंडित और बहुत बड़े जानकार ऋषि-मुनि हमारे संपर्क में आए हैं, जब से केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूं। इसी पार्टी कार्यालय में कल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे। सच्चाई ये है कि वो आपका मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने यहां 3 लोगों के इंटरव्यू लिए।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बस आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि बीजेपी का कौन-कौन उनसे जुड़ा है, लेकिन हमें पता चल गया है। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप जो लिख देंगे, उसे मैं पूरा कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैंने अपने रजिस्टर पर दो बातें लिख दीं। उन्होंने बिना देखे बता दिया कि मैंने क्या लिखा था। मैंने सिर्फ दो ही बातें लिखी थीं कि सपा सरकार बनवाइए और यूपी को खुशहाली के रास्ते पर ले जाइए, जिसे पंडित जी ने एकदम सही बताया, इसलिए हमारे पंडित जी जो कहेंगे, वहीं हम करेंगे। 2012 में उन्होंने सरकार बनवाई थी।

भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 द्विपक्षीय सहयोग के अगले चरण को गति देगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री प्रो. फिलिप बैपटिस्ट के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के बढ़ते दायरे की समीक्षा की गई।

इस वार्ता से भारत-फ्रांस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की गहराई का पता चला, जिसमें दोनों पक्षों ने विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की निरंतर गति पर संतोष व्यक्त किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-फ्रांस की सहभागिता द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बन गई है, जो तकनीकी प्रगति और जन-जन के बीच घनिष्ठ जुड़ाव में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि 2026 को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किए जाने से उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है।

हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रमुख फ्रांसीसी संगठनों के बीच संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्नत सामग्री और डिजिटल विज्ञान में नई पहल के साथ-साथ इस वर्ष शुरू की गई प्रयुक्त गणित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त पहल भी शामिल है।

शुभेन्दु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद बंगाल के पानीहाटी बम ब्लास्ट में पांच भाजपा कार्यकर्ता घायल

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या के कुछ घंटों बाद बम हमले की घटना सामने आई है। इसमें बीजेपी के पांच कार्यकर्ता घायल हो गए। यह घटना कोलकाता से लगे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में हुई। जहां यहा घटना हुई वहां से बीजेपी की नवविर्वाचित एमएलए रत्ना देबनाथ का घर काफी पास है। वह आरजी कर कांड की रेप पीड़िता मृतक डॉक्टर की मां हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा जारी है। कोलकाता के नजदीक आने वाले मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीएम की हत्या के बाद बम अटैक की घटना भी सामने आई है। इसमें पांच बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। बम हमले की यह घटना पीएम चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ घंटे बाद हुई।पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में देर रात हुए बम हमले में बीजेपी के पांच समर्थक घायल हो गए। इत्तेफाक से जिस इलाके में धमाका हुआ वह नई चुनी गई बीजेपी एमएलए रत्ना देबनाथ के घर के पास है। वह आजीकर हॉस्पिटल की रेप पीड़िता की मां हैं।

पीटीआई के मुताबिक बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हत्या के बाद बदले की भावना से हिंसा करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन के पास अनजान हमलावरों ने क्रूड बम फेंके, जिसमें कम से कम पांच बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया। लोकल सूत्रों ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 में दत्ता रोड पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर उन पर बम से हमला किया और मौके से भाग गए। बीजेपी ने दावा किया कि हमलावरों के सत्ताधारी टीएमसी से संबंध था। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी आरे शुभेन्दु अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां उनके पीए को घायल अवस्था में लगा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राथ की हत्या पर कहा कि बंगाल में कानून की हालत देखिए, यहां गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है।

दरिंदों के पनपने के लिए यह सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, चुनाव के नतीजों के बाद जब लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे तब भी हम खून-खराबा होते देख रहे हैं। नई सरकार को यह देखना चाहिए, भाजपा की ओर से यह भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भय का माहौल नहीं रहेगा, लेकिन बंगाल भाजपा के कद्दावर नेता के ढअ की ही हत्या हो जाती है, इसका मतलब है कि बंगाल जहां था वहीं है। सरकार बदली लेकिन हालात नहीं बदले...दोषी को सख्त से सख्त सजा हो और सभी को पता होना चाहिए कि दरिंदे किस पार्टी से है। यह बहुत दर्दनाक घटना है, अपराधी को सजा होनी चाहिए। मामले की जांच होनी चाहिए। बंगाल चुनावों में बीजेपी को 207 और टीएमसी को 80

ग्लोक पिस्टल से हुई ढअ चंद्रनाथ की हत्या! बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंची, एक बार में 17 गोलियों की मैगजीन

शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस पिस्टल से पीए चंद्रनाथ की हत्या की गई है, उसके खोखे मिले हैं। इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के ढअ चंद्रनाथ रथ की हत्या ग्लोक पिस्टल से होने के सबूत मिल रहे हैं। ढअ चंद्रनाथ रथ के शरीर से निकली गोलियां और मौके से मिले खाली खोल 9टट पिस्टल के लग रहे हैं। हालांकि, बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया है।

आधिकारिक रूप से बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि हत्या किस हथियार से की गई है।

पाकिस्तान से बांग्लादेश फिर भारत में सप्लाई, दरअसल, ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लोक पिस्टल पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए भारत में सप्लाई की जाती है। इस पिस्टल का इस्तेमाल आज-कल ज्यादातर गैंगस्टर कर रहे है। इस पिस्टल की खासियत है कि ये एक बार में बर्स्ट फायर कर सकती है। एक बार में 17 गोलियों की मैगजीन चलाई जा सकती है।

बढ़ाई जाएगी शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा, वहीं, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

किया जा रहा आकलन, फिलहाल कैटेगरी सुरक्षा के तहत CRPF कवर मिला हुआ है। इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा में और इजाफे पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा अधिकारी खतरे का आकलन कर रहे हैं। सुरक्षा अपग्रेड को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा।

'कहां के रहने वाले हो? काम के पैसे मिल रहे हैं ना', मजदूरों से मिले सीएम योगी, पूछा हालचाल और खिंचवाई फोटो

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और रूप दिखा, जब वह मजदूरों से मुखातिब हुए। मजदूरों का हाल-चाल जानने के साथ ही उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ बड़े प्रेम से फोटो खिंचवाई।

(जीएनएस)।

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली। जब मंगलवार को वह एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे और वहां मौजूद मजदूरों को देखकर उनसे पूछा, कहां के रहने वाले हो? काम के पैसे समय से मिल रहे हैं ना। मजदूरों ने हां में सर हिलाया, फिर सीएम ने पूछा फोटो खिंचानी है तो आओ, जैसे ही मजदूरों ने सीएम के मुंह से यह सुना

तत्काल उनके पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ खुशी-खुशी ग्रुप फोटो खिंचवाई। यह देख उपस्थित लोग भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर छोटे बच्चों और जानवरों को बुलाते और कुछ करते दिख जाते हैं तो वहीं आम लोगों से मिलते जुलते और संवाद करते भी दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में उनकी कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। मामला मंगलवार को एक कोई पुलिया के उद्घाटन समारोह के दौरान दिखा, जब मजदूरों को काम करते देख उनका हाल-चाल जानने के साथ ही उनके साथ साथ फोटो खिंचाई। इस दौरान सांसद रवि किशन, मेयर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह एवं गोरखपुर विधानसभा की कई विधानसभाओं के विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इतने नजदीक से देखने और उनके साथ फोटो खींचवाने के बाद मजदूरों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और खुशी देखी गई।

सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सफाईकर्मी गिरफ्तार, सगाई टूटने पर युवक को फंसाने के लिए की थी साजिश

(जीएनएस)।

मऊआइमा (प्रयागराज)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने व बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को दबोच लिया गया है। गुरुवार शाम प्रयागराज के मऊआइमा थाने की पुलिस ने धमकी देने के आरोपित शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी नितेश कटियार पुत्र सुरेंद्र कटियार को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त शाहजहांपुर नगर निगम में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत है।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि सगाई टूटने के बाद उसने मऊआइमा निवासी पवन चौरसिया को फंसाने के लिए वाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बताया गया है मऊआइमा थाना क्षेत्र के बरई निवासी पवन कुमार चौरसिया के वाट्सएप नंबर से मुख्यमंत्री के खिलाफ एक

विवादित और धमकी भरा पोस्ट प्रसारित हुआ था।

इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और फिर मोबाइल नंबर के आधार पर पवन को उठा लिया। इंजीनियर पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान शाहजहांपुर निवासी नितेश कटियार से रिश्ता तय हुआ। हालांकि बाद में पवन के परिवार वालों ने शादी नहीं करने की बात कही, जिसको लेकर पवन और नितेश के बीच विवाद हुआ था।

रिश्ता टूटने से नाराज होकर नितेश ने पवन को फंसाने की योजना बनाई और वाट्सएप पर टिप्पणी करते हुए धमकी दी थी। उसमें पवन का नंबर टैग किया था। तब पुलिस ने पवन की तहरीर पर केस दर्ज किया। इंस्पेक्टर मऊआइमा राममूर्ति यादव ने बताया कि धमकी देने के आरोपित सफाईकर्मी नितेश को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

हुमायूं कबीर क्या बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद अब बनवाएंगे बाबरी मस्जिद?

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव के पहले से ही जमकर चर्चा में हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का प्रण लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए इस नेता ने अपनी नवगठित आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के टिकट पर रेजीनगर और नौदा, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की।

अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने जा रही है तब सवाल उठ रहा है कि हुमायुं कबीर क्‍या करेंगे। उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) पार्टी नवगठित भाजपा सरकार के समर्थन करेगी? या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का वादा पूरा करेगी? आइए जानते हैं हुमायूं कबीर की क्या है प्लानिंग?

हुमायूं कबीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " बंगाल बिधानसभा में मैं विपक्ष में बैठूंगा। भाजपा को अधिक सीटें मिल गई है मेरे ख्याल में था कि वो बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरा स्टैंड वैसा ही रहेगा और मैं विपक्ष में बैठूंगा। मैं अपने जिला और क्षेत्र के लिए काम करूंगा और अगर सरकार कोई गलत काम करती है, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि भाजपा क्या गलत कर रही है, ताकि अगले चुनाव में लोग उनके खिलाफ वोट करें।"

मस्जिद निर्माण पर कबीर ने कहा, "ट्रस्ट का जमीन खरीदकर मस्जिद बना रहे हैं, तो कौन रोकेगा।" उन्होंने यह भी कहा, "कोई रोकना चाहेगा, तो संघर्ष होगा। मैं किसी के घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझपर कोई हाथ उठाएगा, तो क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्या?"

दो सीटों पर जीत के बाद क्या बोले हुमायूं? जीत के बाद कबीर ने कहा, "मुर्शिदाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय और ममता बनर्जी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे भेदभाव का जवाब दिया।" उन्होंने कहा कि चार महीने पहले पार्टी स्थापित होने के कारण यह जीत अधिक हौसला बढ़ाने वाली है।

ओवैसी की पार्टी से हुमायूं ने क्यों तोड़ा गठबंधन? बंगाल चुनाव से पहले अखवढ और असदुद्दीन ओवैसी की अक्टक्ट ने गठबंधन किया था, लेकिन बाद में अक्टक्ट ने किनारा कर लिया। इसकी वजह एक वायरल वीडियो था जिसमें कथित तौर पर कबीर को भाजपा नेताओं से अपनी नजदीकियों की बात करते देखा गया था।

हुमायूं जहा बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं वहां भाजपा जीती या हारी? हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का काम शुरू किया था। 4 मई 2026 को घोषित नतीजों में भाजपा ने यह सीट जीती, जहां उसके उम्मीदवार भरत कुमार झावर 13,000 से अधिक मतों से विजयी हुए। कबीर की पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही। वहीं टीएमसी दूसरे स्थान पर रही।

हुमायूं कबीर ने रेजिनगर सीट पर भाजपा के बापन घोष को 58 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर 1,23,536 मत हासिल किए। नौदा सीट पर भी कबीर ने भाजपा के राणा मंडल को 27,943 वोटों से मात दी और 86,463 वोट पाए।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) : 8 मई से शुरू होगा समर थिएटर फेस्टिवल, 38 दिनों में होगा 10 नाटक का

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) रंगमंडल 08 मई से 14 जून 2026 तक अपना वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित करने जा रही है। 38 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैलियों और रंग-रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव का उद्घाटन रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति 'अक्स तमाशा' से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंगनिर्देशक भानू भारती ने किया है। इसकी घोषणा आज एनएसडी परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में की गई।

इस अवसर पर एनएसडी के निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी ने कहा, 'भारत रंग महोत्सव 2026 की अभूतपूर्व सफलता के बाद एनएसडी समर थिएटर फेस्टिवल रंगप्रेमियों के

लिए एक और महत्वपूर्ण रंगोत्सव है । हमारे कलाकारों द्वारा नई सृजनात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किए जा रहे 10 चर्चित नाटकों के माध्यम से दिल्ली का सांस्कृतिक वातावरण और अधिक ऊर्जावान होने जा रहा है । हमें आशा है कि दर्शक इसे भी पिछले वर्ष की तरह सफल बनाएंगे।'

उद्घाटन नाटक 'अक्स तमाशा' ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नाटककार चंद्रशेखर बी. कम्बार के प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक 'सीरी सिम्पिगे' का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अनुवाद वरिष्ठ रंगकर्मी प्रो. राम गोपाल बजाज ने किया है । यह नाटक लोककथा जैसी शैली के माध्यम से भ्रम और सत्य की पड़ताल करता है तथा जुड़वां पात्रों के माध्यम से अपने विषयों को व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। अनुष्ठानिक तत्वों और समकालीन रंगभाषा के मेल से यह आधुनिक दर्शकों तक जटिल विचारों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाता है।

महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य नाटकों में 'बायेन', 'ताजमहल का टेंडर', 'बंदी गली का आखिरी मकान', 'माई री मैं का से कहूँ', 'तमस', 'अंधा युग', 'बाबूजी', 'आधे अधूरे' तथा 'समुद्र मंथन' शामिल हैं, दर्शक इन प्रस्तुतियों के टिकट ऑनलाइन BookMyShow के वेब पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

कौन है वो सपा नेता? 70 की उम्र में 20 साल की लड़की से किया चौथा निकाह, 11 बच्चों का है बाप! दूसरी पत्नी की शिकायत पर होगी हो रही पुलिस जांच

दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद में कैला भट्टा इलाके से निकला यह मामला अब सनसनी का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और दो बार के पूर्व पार्षद 70 वर्षीय हाजी खलील पर 20 वर्षीय युवती यासमीन से चौथा निकाह करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली खुद उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन हैं, जिन्होंने 5 मई को गाजियाबाद कमिश्नर कार्यालय में लिखित शिकायत देकर पूरे प्रकरण को सार्वजनिक कर दिया।

नाजरीन का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि हाजी खलील की आदत बन गई है कि निकाह करना, और उसके बाद हर पत्नी से बच्चे पैदा करना और फिर कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देना या घर से निकाल देना।

उन्होंने कमिश्नर को बताया कि 1991-98 के आसपास जब उनका निकाह हुआ था, तब हाजी खलील ने अपनी पहली शादी और उससे हुए 8 बच्चों की कोई जानकारी नहीं दी थी। नाजरीन से उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा। तीसरा निकाह 2010 में किया गया, लेकिन संतान न होने पर उस पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। अब चौथा निकाह 20 वर्षीय यासमीन (जो स्कूल की छात्रा थीं और हाजी खलील वहां मैनेजर थे) से कर लिया गया है।

नाजरीन का सबसे बड़ा आरोप 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर है। उनका दावा है कि हाजी खलील अब ज्यादातर प्रॉपर्टी चौथी पत्नी यासमीन के नाम ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। जब नाजरीन ने विरोध किया तो उन्हें और उनके बेटे को घर से निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।

4 मई को नाजरीन अपनी बेटियों और बेटे के साथ कैला भट्टा की एक दुकान पर पहुंचीं, जिसे हाजी खलील ने सालों पहले अपने बेटे राशिद के नाम कर रखा था। नाजरीन ने दुकान से राशिद को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। राशिद ने कागजात दिखाए, लेकिन नाजरीन कोई दस्तावेज नहीं दे सकीं। इसके बाद 5 मई को उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयकरन नैय्यर ने जांच का आश्वासन दिया है।

हाजी खलील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नाजरीन उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई की पत्नी थीं, जिनकी 2002 में मौत हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल दो निकाह किए हैं, पहली पत्नी से 8 बच्चे और दूसरी से 3 बच्चे। पूरा मामला नाजरीन की संपत्ति हड़पने की चाल है और पुराना पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा है। हाजी खलील सपा के पुराने चेहरे हैं। उन्होंने 1995 और 2000 में इस्लामनगर वार्ड से सपा टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था। लेकिन उनके नाम पर नगर निगम की 30 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे का पुराना आरोप भी है।

आईपीएल का रोमांच के बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए असली खुशखबरी दिल्ली में आधी रात के बाद भी दौड़ेगी मेट्रो!

(जीएनएस)।

8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल का रोमांच चरम पर होगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए असली खुशखबरी दिल्ली मेट्रो की ओर से आई है। मैच के बाद घर वापसी की चिंता को दूर करते हुए उ्त्फ्ठ ने 'मिडनाइट गिफ्ट' दिया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (DC vs KKR) के मुकाबले को देखते हुए अपनी सेवाओं में विस्तार किया है।

मेट्रो प्रशासन ने सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है ताकि आधी रात को मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को कैब या ऑटो के लिए परेशान न होना पड़े। DMRC ने स्पष्ट

किया है कि यह बदलाव केवल कल यानि 8 मई के लिए है और मैच के समापन समय को देखते हुए टाइमिंग में थोड़ा और बदलाव भी रखा जा सकता है। आइए जानतें हैं इस विशेष व्यवस्था से दिल्लीवासियों को कितनी राहत मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो की नई टाइमिंग :

DMRC द्वारा जारी चार्ट के अनुसार, 12 घंटे वाले (AM/PM) फॉर्मेट में आखिरी मेट्रो का समय इस प्रकार है:

येलो लाइनः समयपुर बादली के लिए रात 12 बजकर 20 मिनट पर और मिलेनियम सिटी सेंटर के लिए रात 11 बजकर 45 मिनट पर।

ब्लू लाइनः द्वारका सेक्टर-21 के लिए रात 12:00 बजे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए रात 11 बजकर 35 मिनट और वैशाली के लिए रात 11 बजकर 45 मिनट पर।

ग्रीन लाइनः कीर्ति नगर और इंदरलोक के लिए आखिरी मेट्रो देर रात 1:00 बजे मिलेगी।

वॉइलेट लाइनः कश्मीरी गेट के लिए रात 11 बजकर 20 मिनट और राजा नाहर सिंह के लिए रात 12 बजकर 25 मिनट पर।

अपग्रेडेड यात्री आरक्षण प्रणाली (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) में अगस्त से रेलगाड़ियों की होगी शिफ्टिंग

(जीएनएस)।

आज रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में 40 साल पुरानी आरक्षण प्रणाली में अपग्रेडेड सिस्टम पर गाड़ियों की शिफ्टिंग होते समय यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे।

1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 साल में कई छोटे बदलाव किए गए। लेकिन अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है । अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इसके क्षमता का विस्तार किया गया है ।

रेल आरक्षण प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे हैं। वर्ष 2002 में भारतीय रेलवे ने टिकटिंग में इंटरनेट का प्रयोग शुरू किया। आज यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि देश की ज्यादातर आबादी खिड़की की ओर रुख नहीं करती। देश में आज जितनी भी टिकटिंग की माँग है, उसका बड़ा हिस्सा (लगभग 88%) ऑनलाइन माध्यम से होता है।

भारतीय रेल का मोबाइल ऐप रेलवन यात्रियों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रेलवन ऐप की शुरूआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। एक साल से कम समय में ही देशभर में अब तक 3.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।

इस ऐप के लोकप्रिय होने के कई

कारणों में से सबसे बड़ा कारण यह है कि यह ऐप देश के आम आदमी को रेल संबंधी सभी जानकारियाँ तो देता ही है, टिकटिंग तथा अन्य सेवाओं से जुड़ी उनकी शिकायतों का भी निपटारा करता है।

आज जब आप अपनी टिकट बनाते हैं, तो रेलवन ऐप आपको यह बताता है कि आपकी वेटिंग में दिख रही टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। टिकट के कन्फर्म होने की सटीक संभावना भी अब आपको एआई के माध्यम से रेलवन ऐप बताने लगा है। यह नई सुविधा इस साल की शुरूआत से ही लागू की गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रेलवन ऐप पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

रेलवन ऐप में इस तरह की कई एकीकृत एवं आधुनिक सुविधाएँ हैं, जो रेल संबंधी अन्य सभी सेवाओं को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जैसे – आरक्षित, अनारक्षित तथा प्लेटफॉर्म आदि विभिन्न प्रकार के टिकटों की बुकिंग, रद्दीकरण तथा रिफंड।

इसके साथ-साथ आपके मौजूदा टिकट की वेटिंग स्थिति की ताजा जानकारी, ट्रेन के आने-जाने का समय, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, ट्रेन के आने-जाने का प्लेटफॉर्म, आपके कोच की स्थिति, तथा रेल मदद जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रेलवन ऐप पर उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप रेलवन ऐप पर भोजन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऐप आपको यह विकल्प देता है कि आपकी सीट तक आपका मनपसंद खाना पहुँच सके। आरामदायक एवं सेवापरक सुविधाओं से लैस यह रेलवन ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

रोजाना इस ऐप के माध्यम से देशभर में 9.29 लाख टिकटें बुक हो रही हैं। इनमें 7.2 लाख टिकटें अनारक्षित तथा अन्य 2.09 लाख आरक्षित टिकटें हैं। अनारक्षित टिकटों में प्लेटफॉर्म टिकट भी शामिल है। एंड्रॉयड तथा आईओएस पर रेलवन ऐप को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जहाँ 3 करोड़ 16 लाख लोगों ने इसे गूगल प्ले स्टोर से अब तक डाउनलोड किया है, वहीं 33.17 लाख लोगों ने इसे ऐपल फोन में डाउनलोड किया है।

देश में यात्रियों के लिए भारतीय रेल एक जीवन रेखा है। भारतीय रेल ने 2024झ25 में यात्रियों के टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% की छूट के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपये है।

टीडीबी-डीएसटी का स्वच्छ परिवहन विजन के अंतर्गत स्वदेशी टाइप- सीएनजी सिलेंडरों के व्यावसायीकरण के लिए एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को समर्थन

(जीएनएस)।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने "टाइप-क्श सीएनजी सिलेंडर के व्यावसायीकरण के लिए विनिर्माण सुविधा की स्थापना" नामक परियोजना के लिए दिल्ली स्थित मेसर्स एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।

इस परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक फिलामेंट वाइंडिंग, ब्लो मोल्डिंग और उच्च दबाव परीक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित टाइप-क्श कंपोजिट सीएनजी सिलेंडरों के उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए एक उन्नत विनिर्माण सुविधा स्थापित

करना है। इस पहल से स्वच्छ परिवहन और उभरते ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत गैस भंडारण प्रणालियों में भारत की घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

टाइप-क्श कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक स्टील सिलेंडरों का अगली पीढ़ी का विकल्प हैं और इनसे वजन में 75 प्रतिशत तक की कमी आती है जिससे वाहन की दक्षता बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। इन सिलेंडरों को जंग-रोधी पॉलीमर लाइनर, अनुकूलित सीएफआरपी लेआउट और उन्नत मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है ताकि बेहतर सुरक्षा व टिकाऊपन सुनिश्चित हो और रिसाव, कंपन न हो। इसका डिजाइन 600 बार से अधिक का विस्फोट दबाव प्राप्त करता है, जो निर्धारित नियामक आवश्यकताओं से काफी अधिक है, जिससे मजबूत परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

यह तकनीक एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और इसे भारत के तेजी से बढ़ते सीएनजी मोबिलिटी इकोसिस्टम को सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परियोजना सरकार के सतत परिवहन, स्वच्छ ईंधन और उन्नत मोबिलिटी घटकों के घरेलू विनिर्माण की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों के अनुरूप भी है।

प्रस्तावित संयंत्र स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करके उच्च दबाव वाले मिश्रित सिलेंडरों के लिए लागत-प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार उत्पादन प्रणाली का निर्माण करेगा। इस परियोजना से आयातित वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और देश में एक सुदृढ़ स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि उन्नत टाइप-क्श कंपोजिट सिलेंडरों का विकास और व्यावसायीकरण भारत के स्वच्छ परिवहन अवसंरचना और स्वदेशी विनिर्माण परितंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

श्रीकृष्ण के चमत्कारों से ज्यादा उनके दिल की बात करती है 'कृष्णावतारम'

एक्शन और रोमांस ड्रामा के बाद अब बॉलीवुड में माइथोलॉजिकल फिल्मों की होड़ मच गई है। इस साल की सबसे चर्चित फिल्म 'रामायण' है लेकिन इसके पहले सिनेमाघरों में आज यानी 7 मई 2026 को 'कृष्णावतारम्-पार्ट 1' रिलीज हुई है, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास भी है।

क्या है 'कृष्णावतारम्-पार्ट 1' की कहानी, जैसे श्रीकृष्ण की बांसुरी से निकली कोई मधुर धुन, जो सुनते ही

मन को कहीं दूर, वृंदावन की गलियों में ले जाती है। ये कहानी भगवान कृष्ण की है लेकिन यहां चमत्कारों से ज्यादा उनके दिल की बात होती है। राधा के साथ उनका प्रेम, रुक्मिणी की समर्पण भरी भावना और सत्यभामा का स्वाभिमान।

भगवान श्रीकृष्ण की खूबसूरत चित्र की कथा, हर रिश्ता एक अलग रंग भरता है और सब मिलकर एक खूबसूरत चित्र बनाता है। फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहना इसके मजा को मार सकता है। कहा जाए कि स्पॉइलर हो सकता है। ऐसे में फिल्म सिनेमाघर में ही देखना चाहिए।

फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी एक्टिंग, एक्टिंग की बात करें तो फिल्म 'कृष्णावतारम्-पार्ट 1' में सिद्धार्थ गुप्ता भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पश्चिम बंगाल का जनादेश

इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता ने लगातार एक ही सरकार को लंबे समय तक बिठाए रखने वाली परंपरा को तोड़ दिया है। 34 साल वाम मोर्चा और 15 साल टीएमसी के बाद जनता ने बता दिया कि सत्ता का लाइसेंस स्थायी नहीं होता। अब 'बंगवासी' को भ्रष्टाचार मुत्त, हिंसा मुत्त, भू-माफिया मुत्त, कटमनी मुत्त, तोला बाज मुत्त, तुष्टिकरण से परे, सिंडिकेट राज मुत्त और अपराध मुत्त बंगाल चाहिए। और इस तरह हुआ बंगाल में तृणमूल सरकार का पतन पश्चिम बंगाल का जनादेश आ चुका है। मतगणना के बाद साफ हो गया कि बंगाल की जनता ने इस बार परंपरा तोड़ दी है। 2011 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के सामने अब अस्तित्व का संकट है, जबकि भारतीय जनता पाटा पर जनता ने इस बार जोखिम लेकर भरोसा जताया है। बंगाल के लोगों ने इस बार केवल सरकार बदलने का पैसला नहीं लिया है उन्होंने उस राजनीतिक संस्कृति को भी नकारा है जहां बयानबाजी, तानाशाही और गुंडागदा शासन पर भारी पड़ रही थी और तुष्टिकरण विकास की जगह ले रहा था। इन चुनाव परिणामों की नींव मतदान से महीनों पहले ही पड़ चुकी थी। मुख्यमंत्री ममता बनजा सहित टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने बंगाल की जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। तृणमूल कांग्रेस तब विवादों के घेरे में आ गई जब पार्टी के एक मंत्री और वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता में एक अखिल भारतीय कुरान प्रतियोगिता के मंच से कहा ह्वजो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वे दुर्भाग्यशाली हैंह्ल और ह्वइस धर्म को गैर-मुसलमानों के बीच फैलाया जाना चाहिए ह्ल एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता का यह वक्तव्य बंगाल की साझा संस्कृति के विरुद्ध था। दुर्गापूजा और ईद साथ मनाने वाले बंगाल में हिंदू बंगाली समाज ने इसे अपनी अस्मिता पर चोट माना। नाराजगी स्वाभाविक थी। मुख्यमंत्री ममता बनजा ने भी इस आग में घी डाला। एक सभा में उन्होंने कहा, ह्वहम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। अगर हम नहीं रहे, तो एक सेकंड में 12 बजा दिए जाएंगे।ह्ल यह बयान एक विशेष समुदाय को संबोधित करते हुए देखा गया। इसका सीधा संदेश यह गया कि बहुसंख्यक हिदू समाज की सुरक्षा सत्ता की कृपा पर निर्भर है। नतीजा यह हुआ कि हिदू बंगालियों में असुरक्षा की भावना घर कर गई। पश्चिम बंगाल के फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त यूपी कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा के बीच हुई तकरार ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। मतदाताओं को डराने की शिकायत पर जब अजय पाल शर्मा टीएमसी नेता के घर पहुंचे तो जवाब मिला, ह्वअगर अफसर ह्यसिंघमह्ल हैं, तो हम ह्यपुष्पाह्ल हैं, झुकेगा नहीं। हम भाजपा के अफसरों से नहीं डरेंगे।ह्ल एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार और उसे ह्वभाजपा का अफसरह्ल कहकर खारिज करना बंगाल के ह्वभद्र मानुषह्ल को रास नहीं आया। अपनी करतूतों को नजरअंदाज कर उल्टे कानून के रखवाले को धमकाना जनता ने गुंडागदा की खुली छूट माना। कानून-व्यवस्था पहले से ही बड़ा मुद्दा थी, इस घटना ने उसे और धार दे दी। वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनजा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, ह्वअगर आपमें हिम्मत है तो मतगणना वाले दिन कोलकाता में रहिएगा, फिर हम देखेंगे ह्ल वे ममता बनजा को चौथी बार सरकार बनने को लेकर आश्वस्त दिखे, पर ह्यखेलाह्ल उल्टा हो गया। अभिषेक बनजा के अभद्र बयान से बंगवासी नाराज हो गए। चुनाव के बीच संवैधानिक पद पर बैठे केंद्रीय मंत्री को इस भाषा में ललकारना मर्यादा का उल्लंघन था। जनता ने इसे अहंकार माना। इसी कड़ी में अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं की ह्वबाहुबलीह्ल छवि और उनके विवादित बयानों ने भी टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर जनता के बीच यही संदेश गया कि सत्ता सेवा नहीं, धमकी का औजार है। ममता बनजा ने इस बार भी बंगाल की जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की भरपूर कोशिश की, पर सफल नहीं हो सकीं। वे एसआईआर, झालमुड़ी, ह्वबाहिरागतह्ल यानी बाहरी लोग, केंद्रीय बलों की तैनाती, बात-बात

उत्तर प्रदेश बनेगा प्रीमियम फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा हब

लखनऊ में 'फ्रूट होराइजन 2026' में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की सहभागिता

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया फल निर्यात में भारत को नंबर वन बनाने का रोडमैप

फलों की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और निर्यात पर सरकार का बड़ा फोकस- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

किसानों की आय बढ़ाने को बनेगा फल सेक्टर का एक्शन प्लान- श्री शिवराज सिंह चौहान

गुणवत्ता से ग्लोबल मार्केट तक: फलों पर राज्य के साथ मिलकर केंद्र सरकार का बड़ा विजन

(जीएनएस)।

लखनऊ के आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH) में आयोजित 'फ्रूट होराइजन 2026' में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता; अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है।

अब फोकस सिर्फ उत्पादन नहीं, गुणवत्ता पर भी, इस महत्वपूर्ण आयोजन में किसानों के साथ ही फल उत्पादन तथा निर्यात सहित इसके कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अगर दुनिया के फल बाजार में आगे बढ़ना चाहता है, तो फलों की गुणवत्ता सुधारना सबसे जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने, निर्यात के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने पर अब विशेष ध्यान देना होगा।

किसानों की आय बढ़ाने को बनेगी टास्क फोर्स, कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि आईसीएआर के वैज्ञानिक संस्थान, निर्यातक, एपीडा और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगी। यह टास्क फोर्स उत्पादकों और निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने तथा एक प्रभावी और समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने का काम करेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

यूपी को मिलेगा क्लीन प्लांट मिशन का बड़ा लाभ, केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने क्लीन प्लांटिंग मैटेरियल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में उक्रल, लखनऊ में आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां आम, अमरूद, लीची और एवोकाडो जैसी फल फसलों के लिए रोगमुक्त और नस्ल-शुद्ध पौध सामग्री तैयार और संरक्षित की जाएगी।

जीरो रिजेक्शन और प्रीमियम क्वालिटी पर जोर, श्री चौहान ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है तो 'जीरो रिजेक्शन' और प्रीमियम क्वालिटी वाले फलों के उत्पादन पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, पैकहाउस, प्रसंस्करण सुविधाएं और निर्यात के लिए व्यावहारिक एसओपी तैयार करके भारतीय बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाई दी जा सकती है।

एफपीओ, क्लस्टर और निर्यात ढांचे से बदलेगी तस्वीर, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने छोटे किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात से जोड़ने में एफपीओ, एफपीसी और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कई नियातोन्मुख क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेडिएशन तथा इंटीग्रेटेड पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाओं, खासकर जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी पहल, को आगे बढ़ाना इस दिशा में अहम कदम होगा।

तमिलनाडु: राज्यपाल ने कहा–विजय की टीवीके बहुमत साबित करे, ऐसे में राजभवन क्या कर सकता है और क्या नहीं

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद चेन्नई की राजनीतिक हलचल अब चुनावी मैदान से निकलकर राजभवन तक पहुंच गई है. अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाला गठबंधन 73 सीटों पर है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) गठबंधन के पास 53 सीटें हैं. किसी एक पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत नहीं मिलने का मतलब है कि सरकार गठन का रास्ता अब गठबंधन बनाने और राज्यपाल की भूमिका पर निर्भर करेगा.

विजय की टीवीके ने औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अभी तक कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है.

संविधान का अनुच्छेद 164 प्रक्रिया को विस्तार से नहीं बताता, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है: ह्वमुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे.ह्ल यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रक्रिया संवैधानिक परंपराओं, राजनीतिक परंपराओं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर तय होती है.

अनुच्छेद और पुराने फैसले

संविधान सरकार गठन में राज्यपाल को अहम भूमिका देता है, लेकिन उनकी शक्तियों की भी सीमाएं हैं. अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान उन्हें विशेष विवेकाधिकार देता है.

अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 174 के तहत वह विधानसभा बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं. अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती और राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ती है.

समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें

लोकतांत्रिक परंपराओं के भीतर रहकर काम करना होगा. अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के निजी फैसलों को कानूनी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन उनके आधिकारिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है.

एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कहा था कि बहुमत साबित करने का एकमात्र सही तरीका विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है. राज्यपाल की निजी राय इससे ऊपर नहीं हो सकती. अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्थिर बहुमत बनने की संभावना हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक होगा.

रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) मामले में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए. विधानसभा बुलाए बिना उसे भंग करना विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल माना जाएगा.

नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियां पूरी तरह निरंकुश नहीं हैं और उन्हें संवैधानिक मयार्दाओं के भीतर रहकर काम करना होगा, किसी राजनीतिक खिलाड़ी की तरह नहीं.

सरकार ने 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग बनाया था. आयोग की 1988 की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए और उनका पद राजनीतिक नहीं दिखना चाहिए.

राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं

परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी यानी इस मामले में टीवीके को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है ताकि वह विधानसभा में बहुमत साबित करे. इसका मतलब होगा कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए और फिर उन्हें तय समय के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़े. त्रिशंकु विधानसभा में यही सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है और इसे एस.आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट का समर्थन भी मिला है.

रामेश्वर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: 'संविधान राज्यपाल से उम्मीद करता है कि चुनाव के बाद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकप्रिय सरकार बनाने की हर संभव कोशिश की जाए.'

राज्यपाल टीवीके से दूसरे दलों के समर्थन पत्र भी मांग सकते हैं, जिससे उनका आंकड़ा 118 तक पहुंच सके. यही नियम किसी संभावित डीएमके-एआईएडीएमके गठबंधन पर भी लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट टालने की कोशिशों के खिलाफ भी चेतावनी दी है. एस.आर. बोम्मई मामले में कोर्ट ने कहा था, 'सरकार की ताकत का आकलन किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं है, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति. इसे विधानसभा में सार्वजनिक रूप से साबित किया जाना चाहिए.'

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम: सीएम योगी ने सुनाई मूक-बधिर खुशी की कहानी, बोले- दिव्यांगों को बस सही अवसर की तलाश

(जीएनएस)।

लखनऊ/कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कानपुर की मूक-बधिर बच्ची 'खुशी' की भावुक और प्रेरणादायक कहानी साझा कर पूरे सभागार को भावुक कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिव्यांगजन में प्रतिभा होती है, आवश्यकता केवल सही अवसर, संवेदना और सहयोग की है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले कानपुर की एक बच्ची, जो न बोल सकती थी और न सुन सकती थी, सिर्फ उनसे मिलने और अपने हाथों से बनाया चित्र भेंट करने के लिए अकेले कानपुर से लखनऊ पहुंच गई थी। इलाज के बाद आज वह बच्ची सुन भी रही है, बोल भी रही है और सामान्य जीवन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, 'मुझे याद है कानपुर की एक बिटिया की कहानी। एक दिन वह बिना किसी को बताए कानपुर से पैदल लखनऊ आ गई। विधान भवन के सामने वह चुपचाप बैठ गई। वह न बोल सकती थी, न सुन सकती थी। उसने अपने हाथ से मेरा एक छोटा सा चित्र बनाकर सामने रख लिया था।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रशिक्षित शिक्षकों ने इशारों में उससे संवाद कर उसका परिवार ढूंढा और उसे वापस कानपुर भेजा। बाद में जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बच्ची को दोबारा बुलाकर उसके इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

दरअसल, कानपुर की रहने वाली खुशी नवंबर 2025 में बिना बताए घर से निकलकर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए लखनऊ पहुंच गई थी। विधान भवन के बाहर रोते हुए मिलने पर पुलिस उसे सुरक्षित थाने ले गई। जांच और चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि बच्ची को सुनने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता है। इस ऑपरेशन पर लगभग छह से सात लाख रुपये का खर्च आना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और एक फाउंडेशन के सहयोग से उसके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई गई।

26 जनवरी 2026 को खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब खुशी आवाजें सुन पा रही है और उसने टूटे-फूटे शब्दों में बोलना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे- 'थैंक यू योगी जी।' डॉक्टरों के अनुसार नियमित स्पीच थैरेपी और अभ्यास के बाद आने वाले कुछ महीनों में उसकी बोलने की क्षमता और बेहतर होगी तथा एक वर्ष के भीतर वह सामान्य बच्चों की तरह बातचीत कर सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि अगर हम दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करते हैं तो यह अन्याय है। हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, बस सही अवसर और सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के बाद खुशी ने सबसे पहले उस पुलिस इंस्पेक्टर का चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया, जिन्होंने लखनऊ में उसकी मदद की थी। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता का यह भाव समाज को संवेदनशील बनाने की प्रेरणा देता है। खुशी की कहानी इन्हीं प्रयासों का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है।

आईपीएल में ई-सिगरेट और गर्लफ्रेंड मामलों पर शिकंजा कसने की तैयारी, एक्शन मोड में आई बीसीसीआई का बड़ा ऐलान

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के दौरान मैदान के बाहर घट रही घटनाओं ने बीसीसीआई (इउउक) की चिंता बढ़ा दी है। खिलाड़ियों के साथ अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही और होटल रूम्स में बाहरी लोगों के प्रवेश के मामलों को देखते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड ने अब कुछ कड़े नियम बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब यह क्रिकेट लीग कम और अय्याशी का अड्डा ज्यासा नजर आ रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने अब सख्ती से पेश आने की योजना बनाई है। देवजीत सैकिया ने कई अहम बातों का जिक्र किया है।

रक्षा प्रोटोकॉल में चूक: सैकिया ने कहा कि टीम के सदस्यों के साथ कई ऐसे अनधिकृत लोग घूम रहे हैं, जिनके पास अनुमति नहीं है। यह सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा जोखिम है।

होटल और रूम एंट्री पर रोक: बोर्ड के संज्ञान में आया है कि बाहरी लोग खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के कमरों तक पहुंच रहे हैं। देवजीत सैकिया के अनुसार यह हमारे एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल के पूरी तरह खिलाफ है।

अधिकारियों का हस्तक्षेप: केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीम मालिकों और अधिकारियों द्वारा भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में खिलाड़ियों से मेल-जोल बढ़ाने के मामले सामने आए हैं।

नियमों का उदारीकरण: बोर्ड ने माना है कि पिछले कुछ समय में नियमों के पालन में ढिलाई बरती गई है, जिसे अब तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है।

देवजीत सैकिया ने घोषणा की है कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मिलकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करेंगे। यह एडवाइजरी सभी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह होगी। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो बीसीसीआई और आईपीएल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।

गौरतलब है कि प्लेयर्स को खुलेआम गर्लफ्रेंड्स के साथ होटल में देखा जाता है। टीम बस में भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा खुलेआम ई-सिगरेट और अन्य गतिविधियां देखी जा रही है। यह एक छपरी क्रिकेट लीग नजर आ रही है।

तमिलनाडु में भाजपा एक सीट पर क्यों हुई ढेर? वोट शेयर भी गिरा, क्या भारी पड़ा अन्नामलाई फैक्टर?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में कई बड़े उलटफेर किए, लेकिन इखढ के 'दक्षिण विजय' के दावों पर पानी फेर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने अकेले दम पर 11.24% वोट शेयर हासिल कर राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, वहीं 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर करीब 3% तक सिमट गया।

इतना ही नहीं, 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी केवल एक सीट जीत सकी। यह गिरावट सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने तमिलनाडु में भाजपा की रणनीति, गठबंधन के फैसलों और अन्नामलाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विस्तार से पढ़ें हार की पूरी इनसाइड स्टोरी

2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए तमिलनाडु में एक मोरल विक्ट्री की तरह देखा गया था। पार्टी ने द्रविड़ दलों ऊटड और अक्रअऊटड से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 11% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उस समय बीजेपी ने खुद को राज्य में तीसरी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। उस प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी। लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल उलट रहे।

2024 की 'प्रगति' का 2026 में 'पतन' होने के पीछे कई प्रमुख कारण रहे:

इस बार भाजपा, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी। सूत्रों का कहना है कि अन्नाद्रमुक ने भाजपा को वे 27 सीटें दीं, जहां या तो द्रविड़ दलों का गढ़ था या जहां भाजपा की जमानत बचाना भी मुश्किल था। खुद के दम पर लड़ने के बजाय गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनने से भाजपा का अपना स्वतंत्र वोट बैंक बिखर गया।

बिहार शपथ ग्रहण में वंदे मातरम् को भूल सीधे बजाया राष्ट्रगान, नए नियम का क्या हुआ?

(जीएनएस)।

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार 7 मई 2026 को आयोजित बिहार की नई ठऊअ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक तौर पर जितना बड़ा था, उतना ही एक प्रोटोकॉल विवाद की वजह से भी चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 32 नेताओं के शपथ लेने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे।

लेकिन बिहार मंत्रिमडल विस्तार का समारोह शुरू होते ही सीधे राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजा दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से जारी

दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि सरकारी कार्यक्रमों में अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हों तो शुरूआत 'वंदे मातरम्' से होगी।

गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। मंच पर ठऊअ के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और हजारों समर्थक मैदान में पहुंचे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्रगान बजा और सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि तय प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2026 में सरकारी कार्यक्रमों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाएं, वहां कार्यक्रम की शुरूआत 'वंदे मातरम्' से होगी और समापन राष्ट्रगान से किया जाएगा। इसमें वंदे मातरम के 6 स्टेनजा बजाने की बात भी कही गई थी।

नए नियमों के मुताबिक अब बड़े सरकारी कार्यक्रमों, राज्यपाल और राष्ट्रपति के आगमन समारोह, ध्वजारोहण और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में 'वंदे मातरम्' का पूरा छह अंतरों वाला संस्करण बजाना अनिवार्य किया गया था, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड है।

डिस्को, डेटिंग ऐप और खौफनाक ट्विस्ट, 'बंदर' में दिखेगा बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार

बॉबी देओल पिछले कुछ समय से लगातार अपने दमदार किरदारों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। 'एनिमल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब बॉबी देओल बिल्कुल अलग अंदाज में बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'बंदर' का

टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

आपको बता दें कि फिल्म 'बंदर' का दमदार टीजर आज यानी 7 मई 2026 (गुरवार) को रिलीज किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और पहली बार बॉबी देओल उनके साथ काम कर रहे हैं।

टीजर देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म आम बॉलीवुड मूवीज से काफी अलग होने वाली है।

'भर्ती में न सिफारिश, न भ्रष्टाचार सिर्फ योग्यता का सम्मान', सीएम योगी का सीधा संदेश

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए.

इस अवसर पर लोकभवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिशन रोजगार' के अंतर्गत प्रदेश सरकार लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रही है. अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. पूरी प्रक्रिया में किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई.

साफ नीयत और स्पष्ट नीति का परिणाम- सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षा के बाद भी किसी स्तर पर सिफारिश या अनैतिक साधनों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी. इसी साफ नीयत और स्पष्ट नीति का परिणाम है कि आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है.

'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियां पैसों, जाति, मत, मजहब और क्षेत्र देखकर होती थीं, जिससे योग्य नौजवानों का शोषण होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योग्यता ही चयन का आधार बनी है. उन्होंने कहा कि किसी योग्य अभ्यर्थी की जगह घूसखोर व्यक्ति व्यवस्था में आ जाता, तो वह अगले 30-35 वर्षों तक पूरे सिस्टम को घुन की तरह खोखला करता.

इसलिए सरकार ने पहले दिन से ही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावनाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण आज यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है.

15 दिनों के अंदर चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपी के नौजवानों को निष्पक्ष, पारदर्शी व सहज प्रक्रिया से सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी.

सीएम योगी ने कहा कि हमने अलग-अलग आयोगों व बोर्डों को जवाबदेही सौंपी और तकनीक का उपयोग कर हर योग्य नौजवान के साथ न्याय सुनिश्चित किया. इसी का परिणाम है कि हमने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं. पिछले 15 दिनों के अंदर यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है.

यूपी को बना दिया गया था भ्रष्ट-गुंडा-अराजक प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि याद कीजिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश. देश-दुनिया में लोग यूपी का नाम सुनते ही शक की निगाह से देखते थे, दस कदम पीछे हट जाते थे. उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट, गुंडा और अराजक प्रदेश बनाकर हर यूपीवासी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था.

उन्होंने आगे कहा कि लेकिन, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अब आप कहीं भी जाएं, यूपी का नाम सुनते ही सामने वाले का चेहरा चमक उठता है, वह स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है. यह है परसेप्शन का बदलाव और परिणाम भी उसी के अनुरूप हैं.

प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व अर्थव्यवस्था को तीन गुना किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व समग्र अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है. यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है. यह सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला, किसानों को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला और समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने वाला प्रदेश बन गया है.

3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले एमएसएमई क्षेत्र लगभग बंद पड़ा था, कोई प्रोत्साहन नहीं था, चारों तरफ अव्यवस्था और हताशा थी. आज देश में सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्तर प्रदेश में हैं. 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं.

सीएम ने बताया कि गत वर्ष यूपी में 4000 से अधिक बड़े उद्योग आए और पिछले 9 वर्षों में बड़े उद्योगों की संख्या 14,000 से बढ़कर 32,000 से अधिक हो गई है. जिस यूपी को पहले देश के बॉटम-3 राज्यों में गिना जाता था, आज टॉप-3 राज्यों में शामिल है.

आयुष के माध्यम से लाए जा सकते हैं चमत्कार

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष हेल्थ टूरिज्म को आकर्षित करने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है. इसके माध्यम से चमत्कार लाए जा सकते हैं. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को गांव-गांव में और बेहतर बनाना है. उपचार की पारंपरिक विधाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है.

मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन के लिए किसानों से संवाद स्थापित करना है. आज 202 प्राध्यापक, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि आप सब आयुष विभाग को और गति देंगे. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उद्योग की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपावर

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग बड़ा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है. अनुकूल वातावरण व नीतियों से यूपी में लगातार बड़े निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, इन उद्योगों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा इसके अनुदेशकों की जिम्मेदारी है.

व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 150 से अधिक आईटीआई को आधुनिक बना दिया है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. हम कुशल प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन व अन्य टेक्नीशियन भी तैयार कर रहे हैं. आज नियुक्त होने वाले 272 ट्रेंड अनुदेशक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

हर दिव्यांगजन में प्रतिभा बस सही प्लेटफॉर्म चाहिए- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण नाम भी प्रधानमंत्री ने दिया है. कोई भी व्यक्ति किसी कारण से दिव्यांगता का शिकार हो सकता है. हमारे मन में उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए. हर दिव्यांगजन में प्रतिभा है, बस उसे सही प्लेटफॉर्म चाहिए.

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. पेंशन सुविधा दी, दो दिव्यांगजन विश्वविद्यालय स्थापित किए, हर कमिश्नरी मुख्यालय पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष केंद्र खोले गए और बंद पड़े डीआरसी (डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स) को पुनः चालू किया गया.

इस अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण नरेन्द्र कुमार कश्यप, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', तीनों विभागों के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, डॉ हरिओम और रंजन कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

सहे ताने, उठायी दिक़्कतें, पर नहीं हुए टस से मस ; योगी को पीएम बनते देखने के लिए सुभाष ने बढ़ाए नाखून

(जीएनएस)। लखनऊः लखनऊ के रानीगंज निवासी सुभाष श्रीवास्तव ने एक अनोखा संकल्प लिया है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने प्रण किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक वे अपने नाखून नहीं कटवाएंगे. उनके एक हाथ के नाखून अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

सुभाष के अनुसार, इससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और राम मंदिर दर्शन की मन्नत पूरी होने तक भी नाखून बढ़ाए थे. जब उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो गई, तब उन्होंने नाखून कुछ छोटे किए थे, लेकिन अब योगी के लिए फिर से नाखून बढ़ाना शुरू कर दिया है.

जानकारी देते सुभाष श्रीवास्तव. (श्रींङ्ग उ१्र३िः एळश इँ१३)

11 साल से जारी है यह कठिन तपस्याः सुभाष श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने 26 मई 2014 को मोदी जी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में नाखून रखने का सिलसिला शुरू किया था. अब उनके इस संकल्प को लगभग 11 साल 11 महीने और 12 दिन पूरे हो चुके हैं. शुरूआत में उनके माता-पिता ने दाढ़ी, बाल और नाखून बढ़ाने पर काफी एतराज जताया था क्योंकि वे बाबा बनना चाहते थे. वह याद करते हैं कि 1992 में जब वे पहली बार इतने बड़े नाखूनों के साथ अयोध्या पहुंचे थे, तो वहां सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेरे में लेकर विशेष दर्शन कराए थे. उस समय मणिराम छावनी के संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद उनकी आस्था इस संकल्प में और गहरी हो गई.

किसी की मदद नहीं लेते हैं सुभाषः इतने लंबे नाखून होने के बावजूद सुभाष अपने दैनिक कार्य स्वयं ही निपटाते हैं और किसी की मदद नहीं लेते. उन्होंने बताया कि अब उन्हें गिलास पकड़ने, प्लेट उठाने और कपड़े पहनने की आदत पड़ गई है, हालांकि फुल आस्तीन की शर्ट पहनने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है. उनके घर में पत्नी और बच्चे अक्सर इन नाखूनों को हटाने का दबाव बनाते हैं, लेकिन सुभाष इसे अपनी जिद और मान्यता मानते हैं. उनका मानना है कि नाखून बढ़ाने से उनकी मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है. यहां तक कि कानपुर में एक डॉक्टर ने हाथ कमजोर होने की चेतावनी दी थी, लेकिन वे नियमित व्यायाम से खुद को फिट रखते हैं.

विरोध के बाद भी नहीं डिगा इरादाः सुभाष जब भी बाजार या किसी सार्वजनिक स्थान पर निकलते हैं, तो लोग उनके नाखूनों को देखकर चौंक जाते हैं.

2027 चुनाव से पहले यूपी सरकार के प्लेटर से नॉन-वेज गायब!

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक व्यंजन' (ODOC) योजना के तहत पूरे राज्य के 75 जिलों के लिए 208 व्यंजनों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। योजना का मकसद डउ्ढढ की तर्ज पर स्थानीय व्यंजनों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात के जरिए वैश्विक पटल पर ले जाना है। ₹150 करोड़ का बजट भी मंजूर। लेकिन इस प्लेटर पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक भी नॉन-वेज व्यंजन शामिल नहीं किया गया।

लखनऊ को रेवड़ी, आम के उत्पाद, चाट और मलाई मक्खन मिले हैं। आगरा को पेठा और दालमोठ। मथुरा को पेड़ा-माखन मिश्री। वाराणसी को ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लस्सी और बनारसी पान। सुल्तानपुर को पेड़ा-समोसा-जलेबी, बाराबंकी को चंद्रकला, अमेठी को समोसा-गुलगुला, अयोध्या को चंद्रकला-बालूशाही-दही। पूरी सूची में मीठे, चाट, समोसे, कचौड़ी, इमरती, पेड़ा, हलवा, गुड़-खीर जैसे शाकाहारी आइटम्स ही छाए हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या-क्या गायब?

जिन व्यंजनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, वे यूपी की पाक-परंपरा की पहचान रहे हैंः लखनऊः गलौती कबाब, टुंडे कबाब, अवधी बिरयानी, निहारी कुलचा, काकोरी कबाब, मुरादाबादः मुरादाबादी बिरयानी, रामपुरः मटन कोरमा, सीख कबाब, बरेलीः मटन के लोकप्रिय व्यंजन

ये व्यंजन न सिर्फ अवधी-मुगलई संस्कृति के प्रतीक हैं, बल्कि दुनिया भर में यूपी की पाक-विरासत का पर्याय रहे हैं। UNESCO (यूनेस्को) ने 31 अक्टूबर 2025 को लखनऊ को आधिकारिक तौर पर 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का दर्जा दिया है।

विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रिया

प्रसिद्ध खाद्य इतिहासकार और Cuisine Society of India के अध्यक्ष पुष्पेश पंत ने इसे 'अधूरा कदम' बताया। उन्होंने ढळक को दिए बयान में कहा, 'यह आधा-अधूरा कदम कट्टरता की बू देता है। संक्षेप में, अज्ञानतापूर्ण बकवास है।' पंत ने साफ कहा कि वे शाकाहारी व्यंजनों की भी सराहना करते हैं, लेकिन 'चुनिंदा भेदभाव क्यों?'

सरकार का जवाबः 'जानबूझकर नहीं किया, सूची लचीली है'

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि यह कोई सोचा-समझा फैसला नहीं है। 'भविष्य में सिफारिश मिलने पर इन्हें शामिल किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य किसी एक लोकप्रिय व्यंजन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पैकेजिंग, बिक्री और प्रचार के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है।' सूत्रों के मुताबिक सूची लचीली है - स्थानीय सुझाव और जनमांग के आधार पर मुख्यमंत्री की मंजूरी से कभी भी बदलाव हो सकता है, कैबिनेट की जरूरत नहीं।

208 व्यंजनों की लिस्ट, सुल्तानपुर- पेड़ा, समोसा, कढ़ाई पूरी, लाल पेड़ा, जलेबी, बाराबंकी- चन्द्रकला, लाल पेड़ा, अमेठी - समोसा, गुड़ की खीर, गुलगुला, अम्बेडकर नगर - बालूशाही, चाट, खजला, देवीपाटन मण्डल (गोण्डा) -दही बड़ा, बहराईच- चमचम, कचौरी, बलरामपुर- नारियल की बर्फी, कलाकंद, घमंजा, चाट, श्रावस्ती - इमर्ती, लखनऊ - रेवड़ी, आम उत्पाद, चाट, मलाई मक्खन, आगरा- पेठा, दालमोठ, फि रोजाबाद- टिक्की, कचौरी, अलीगढ - डेयरी उत्पाद और कचौरी, मथुरा- पेड़ा और माखन मिश्री, मुरादाबाद - दाल के व्यंजन, हांडी का हलवा, हरदोई - आलू पूड़ी, लड्डू, लौझड़, लखीमपुर खीरी- केला, गुड़, खोया पेड़ा, खीर मोहन, रसगुल्ला, रायबरेली - मसाले, सीतापुर- माखन मलाई, समोसा, मिर्ची पकौड़ा, पेड़ा, उन्नाव- काला जामुन, समोसा, कुशली, त्रिलोक परी, अयोध्या - चंद्रकला, बालूशाही, दही , जमगढ़ - सफेद गाजर का हलवा, महोबा - खजूर का गुड़, मेरठ- गजक और रेवड़ी, प्रयागराज- कचौरी, समोसा और रसमलाई, हमीरपुर -बुंदेली दाल से तैयार की गई तैयारियां, वाराणसी - ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लस्सी और बनारसी पान, यह सूची ठीक 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिसंबर 2025 में योजना की घोषणा की थी और 24 जनवरी 2026 को अमित शाह ने लखनऊ में लॉन्च किया। आलोचकों का कहना है कि अवधी-मुगलई मिली-जुली संस्कृति को शाकाहारी 'सफेदी' में रंगने की कोशिश की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने श्रम संहिता के तहत आने वाले श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया

देश भर में 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी

डॉ. मांडविया ने कहा, "भारत श्रम संहिता के तहत आने वाले गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने वाले पहले देशों में से एक बन गया है"

केंद्रीय मंत्री ने भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत होने पर जोर दिया, जिससे लगभग 94 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है

ईएसआईसी कवरेज एक दशक पहले लगभग 7 करोड़ लाभार्थियों से बढ़कर आज लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गया है: डॉ. मांडविया

(जीएनएस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली के बासैदारापुर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। यह देश के श्रमबल के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश भर के श्रमिकों के लिए गरिमा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी को दशार्ता है।

इस अवसर को "श्रम शक्ति" के सम्मान को समर्पित दिन बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रोजगार सृजन और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से "श्रम शक्ति" और "युवा शक्ति" को सशक्त बनाने के लिए काम किया है।

श्री मांडविया ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जो एक दशक पहले लगभग 30 करोड़ लोगों से बढ़कर आज लगभग 94 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गया है, यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि ईएसआईसी के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या एक दशक पहले लगभग 7 करोड़ थी, जो आज बढ़कर लगभग 15 करोड़ हो गई है।

श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि अब देश भर में 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच के माध्यम से शीघ्र निदान से गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि जांच शिविरों के दौरान पहचानी गई बीमारियों का इलाज और दवाएं ईएसआईसी सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

चार श्रम संहिताओं के तहत प्रमुख श्रम सुधारों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, और महिलाओं के लिए घर से काम करने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि जहां दुनिया भर के देश अब भी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा ढांचे के तहत लाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने नए श्रम संहिता के माध्यम से सक्रिय रूप से उनके समावेश को सुनिश्चित किया है।

डॉ. मंडाविया ने आगे कहा कि खतरनाक व्यवसायों में लगे श्रमिकों और यहां तक कि 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अब ईएसआईसी के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले श्रमिकों की उपेक्षा की जाती थी और उनकी बात अनसुनी कर दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी समस्याओं को प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ दूर किया किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जांच पहल देश के कार्यबल के लिए गरिमा, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने दिल्ली में जनगणना जागरूकता के लिए छह एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई

(जीएनएस)। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (RG & CCI) ने आज जनगणना भवन, नई दिल्ली से छह जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई। यह पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनगणना 2027 के पब्लिक आउटरीच अभियान के हिस्से के रूप में की गई है, जो जनगणना 2027 के जारी पहले चरण झ्र अर्थात मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) के लिए है।

ये जनगणना जागरूकता वैन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगी और जनगणना में भागीदारी, स्व-गणना (SE) सुविधा, जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताओं, तथा फील्ड विजिट के दौरान प्रगणकों के साथ जनता के सहयोग के महत्व से जुड़े संदेशों का प्रसार करेंगी। इस अभियान का उद्देश्य जानकारी का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना, जन जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनगणना कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) का कार्य जारी है। NDMC और छावनी बोर्ड क्षेत्रों में, 15 अप्रैल, 2026 को लछड स्व-गणना (SE) पूरी होने के बाद, प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर फील्ड विजिट का कार्य 16 अप्रैल, 2026 से शुरू हुआ, जो 15 मई, 2026 तक संपन्न हो जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (MCD क्षेत्रों) में, वर्तमान में स्व-गणना (SE) का कार्य जारी है। निवासी 1 मई से 15 मई, 2026 तक की निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक जनगणना पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (SE) कर सकते हैं। इसके बाद, 16 मई से 14 जून, 2026 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का काम किया जाएगा।

जिन निवासियों ने स्व-गणना पूरी कर ली है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी स्व-गणना आईडी (SE ID) अपने पास तैयार रखें और प्रगणक के आने पर इसे उनसे साझा करें।

जनगणना 2027 में स्व-गणना (SE) सुविधा पहली बार शुरू की गई है जिसे जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक, 23 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में लगभग 92 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक स्व-गणना (SE) पूरी कर ली है।

जनगणना 2027 के मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना चरण में एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र करना शामिल है, जिसमें परिवारों के विवरण, आवास की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्तियों से संबंधित 33 निर्धारित प्रश्न शामिल हैं। एकत्र किया गया डेटा सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में आज से मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना चरण का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के निवासी 7 मई से 21 मई, 2026 तक की निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (रए) कर सकते हैं। इसके बाद, 22 मई से 20 जून, 2026 तक घर-घर जाकर क्षेत्रीय कार्य किए जाएंगे।

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना चरण स्व-गणना वर्तमान में तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली (टउऊ), महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में चल रही है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली (NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र), गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और उत्तराखंड में प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर विज़िट करने का काम चल रहा है।

जनगणना अधिनियम, 1948 के अनुसार, जनगणना के दौरान एकत्रित समस्त डेटा पूर्णतः गोपनीय रहता है, और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास नियोजन के लिए किया जाएगा। अधिसूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध है कि वे मकानसूचीकरण कार्यों के दौरान प्रगणकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।

प. बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर पाकिस्तान में खलबली ?

गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मोहसिन नकवी के कंधे पर आईएसआई-एलईटी घुसपैठ की आशंका?

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के महज 48 घंटे बाद एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। BJP नेता और संभावित मुख्यमंत्री रेस में चल रहे सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई।

9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले एक सुरक्षा अलर्ट सामने आया है। बांग्लादेशी वरिष्ठ पत्रकार सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने (पूर्व ट्विटर) पर दावा किया है कि पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी शुक्रवार 8 मई को ढाका पहुंच रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में BJP की ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री का बांग्लादेश दौरा क्यों? क्या यह सामान्य कूटनीति है या बंगाल की नई सत्ता और भारत की पूर्वी सीमा सुरक्षा के लिए नया खतरा? चौधरी के अनुसार, नकवी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG342 से 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका पहुंचेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे...

सैयद मोहसिन रजा नकवी, मोहम्मद अफजल, सुमैर अहमद सैयद, सलमान नसीर, मुहम्मद सलमान लियाकत, मुहम्मद साद बिन उबैद, राणा हुसैन ताहिर, आमिर मीर, बिलाल अफजल

सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल में क्रकके कुछ सदस्य और कम से कम पांच लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े विस्फोटक विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग ढाका पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से जेसोर जिले के बेनापोल (भारत से सटा संवेदनशील बॉर्डर) की ओर बढ़ेंगे और गुप्त रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं।

यह दौरा संयोग नहीं लगता। बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान से रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ठीक वैसे जैसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान शुरू हुए थे। इसी सप्ताह बांग्लादेश ने अपने वाणिज्य, गृह और लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पाकिस्तान भेजा था। यह बांग्लादेश की आजादी के बाद पहला ऐसा मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका पूरा खर्च पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का यह दौरा दोनों देशों के बीच प्रशासनिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है।

इखढ की जीत और सुरक्षा का संवेदनशील समय

यह सब पश्चिम बंगाल में इखढ की 206 सीटों वाली भारी जीत के महज दो दिन बाद हो रहा है। शपथ ग्रहण 9 मई को है। उसी दौरान इखढ नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि, पुलिस ने अभी इसे किसी बड़ी साजिश से नहीं जोड़ा, लेकिन समय का संयोग राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

भारत-बांग्लादेश सीमा (लगभग 2,200 किमी) पहले से ही घुसपैठ, तस्करी और स्लीपर सेल्स के लिए संवेदनशील रही है। छीळ जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लंबे समय से बांग्लादेश को भारत में घुसपैठ का रास्ता बनाने की कोशिश करते रहे हैं।

यह मामला सिर्फ एक मंत्री का दौरा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का आईना है। बंगाल में इखढ की सत्ता आने के बाद अवैध घुसपैठ पर सख्ती, ठफ्ढ-उअअ जैसे मुद्दों और पूर्वी सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान से पुराने रिश्ते फिर से गर्म कर रही है। अभी भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी सरकारी एजेंसी ने इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस और इरऋ सीमा पर निगरानी बढ़ा चुकी है।

सवाल यही हैः क्या यह महज कूटनीतिक दौरा है या बंगाल की नई राजनीतिक हकीकत के बीच पूर्वी मोर्चे पर कोई नया खेल? आगे की जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया पर सबकी नजर है।